पूर्ण बेंच

समक्ष एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश., पी.सी. जैन और डी.एस. तेवतिया न्यायाधीश.

वाहिदी बेगम- *याचिकाकर्ता।*

बनाम

भारत संघ और अन्य, - *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1975 *का* 5639 .

29 मई, 1980.

*भारत का संविधान 1950 (*संविधान द्वारा यथासंशोधित) (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 - *अनुच्छेद 226-* विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम *(1954 का XLIV*)-धारा 33 - शब्द '*अनुच्छेद* 226 *के खंड (3)* में होने वाला कोई अन्य *उपाय- इस तरह के उपाय का अर्थ- क्या एक प्रभावी उपाय होना चाहिए - धारा* 33 के तहत उपाय - *क्या यह अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर रोक लगाने के लिए प्रभावी है*।

यह माना गया है कि संसद की मंशा है कि भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के खंड (3) में परिकल्पित उपाय पर्याप्त, वास्तविक और भ्रामक नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 226 के खंड (1) के उप-खंड (बी) और (सी) से ही कम है। उपखंड (ख) और (ग) के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कानून के कुछ संवैधानिक या सांविधिक उपबंधों के उल्लंघन अथवा उसके अधीन कार्यवाहियों में प्राधिकारी द्वारा की गई अवैधता के कारण हुई क्षति के निवारण के लिए किया जा सकता है और जहां ऐसी क्षति पर्याप्त प्रकृति की हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप न्याय में पर्याप्त विफलता हो। लेकिन अनुच्छेद 226 के खंड (3) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लगाए गए और प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसी चोट के लिए उसमें दिए गए उपाय का सहारा लेकर कानून के तहत निवारण किया जा सकता है। लेकिन जहां ऐसा उपाय निवारण प्रदान करने में असमर्थ है जैसा कि उप-खंड (बी) और (सी) के तहत परिकल्पित है, तो निश्चित रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र को छीनने का संसद का इरादा कभी नहीं हो सकता है।

और पीड़ित व्यक्ति को उस निरर्थक, भ्रामक या अप्रभावी उपाय का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है और अंततः उसे एक अपूरणीय और अपूरणीय चोट पहुंचाता है। 'उपाय' शब्द अपने आप में यह मानता है कि यह वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए और यदि 'कोई अन्य उपाय' शब्द 'यह अर्थ नहीं दिया जाता है, तो किसी दिए गए मामले में खंड (बी) और (सी) का पूरा उद्देश्य निराश हो सकता है। यदि कोई वैकल्पिक उपाय खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित चोट का निवारण प्रदान नहीं कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 (3) रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि, प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर देखना होगा और यदि वैकल्पिक उपाय प्रदान करने वाले किसी विशेष क़ानून के प्रावधान पर विचार करने के परिणामस्वरूप, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित चोट के निवारण के लिए ऐसा प्रावधान कोई उपाय नहीं है, तो निश्चित रूप से एक रिट एक उचित उपाय होगा। (पैरा 12)।

माना गया कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 33 के तहत याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे सुना जाना चाहिए, कि उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और इस प्रावधान के तहत कार्यवाही एक संशोधन नहीं है, बल्कि केवल एक अभ्यावेदन है जो केंद्र सरकार को विचार के लिए दिया जाता है जिसे बिना किसी बोलने के सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। आदेश। इस प्रकार का उपाय न केवल प्रभावहीन है, बल्कि अनुच्छेद 226 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (सी) के तहत परिकल्पित चोट को दूर करने में असमर्थ है।

(Para 24).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि:*
-

1. *मामले के रिकॉर्ड उन्हें रिट याचिका के उचित निपटान के लिए तलब किए जाने से खुश कर सकते हैं;*
2. *मुख्य निपटान आयुक्त के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ उप सचिव के आक्षेपित निर्देशों को रद्द करते हुए उन्होंने निर्देश जारी किया कि याचिकाकर्ता ने अपने मूल क्षेत्र के साथ-साथ उसे आवंटित किए जाने वाले वैकल्पिक क्षेत्र के मूल्यांकन के समान मानक को लागू करके कानून के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया। प्रतिवादियों को एक निर्देश भी जारी किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जिसके लिए उसे पिछले कई वर्षों से अपनी संपत्ति के लाभ से अवैध रूप से वंचित किया गया है;*
3. *कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए;*
4. *इस याचिका की लागत का भुगतान किया जाए।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि अनुलग्नक पी-1 *से पी-5 और* पी-7 *और पी-8* की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए*।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से बीएस वासू के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. वासु।

उत्तरदाताओं के लिए नौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी.

निर्णय

पी.सी. जैन. न्यायाधीश

1. सुश्री वाहिदी बेगम के पास; भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के साथ-साथ हरियाणा सरकार के उप सचिव, पुनर्वास विभाग द्वारा जारी निर्देशों को रद्द करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए यह याचिका दायर की गई है।

2.याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता खान साहिब अब्दुल गफूर खान के पास गांव मोहम्मदपुर सोतार और मेघनवाली, तहसील फतेहाबाद, जिला हिसार में कृषि भूमि थी कि खान साहिब अब्दुल गफूर खान देश के विभाजन के समय पाकिस्तान नहीं गए थे और 1955 में हिसार में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह एक भारतीय नागरिक के रूप में भारत में रहे थे। उनके आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उनकी संपत्ति को बहाल कर दिया गया था, कि उनकी मृत्यु पर याचिकाकर्ता इन दो गांवों में उनके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि में एक-चौथाई हिस्सा लेने में सफल रहा, कि याचिकाकर्ता की अपने पिता की संपत्ति में से अपने हिस्से के आवंटन के लिए पात्रता 112-4 जे स्टैंडर्ड एकड़ हो गई, कि नहर सिंचाई के कारण भूमि का मूल्य बढ़ गया है। याचिकाकर्ता को आवंटन के बदले 29.14 मानक एकड़ आवंटित किया गया था, जिसके लिए वह हकदार थी, कि यह आवंटन हरियाणा सरकार, पुनर्वास विभाग के उप सचिव द्वारा 30 दिसंबर, 1968 को जारी पत्र संख्या 1 (33) जी-एल 23837-42/68 में जारी निर्देशों के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने आवंटन का विरोध किया और मुकदमा मुख्य निपटान आयुक्त तक विफल रहा। हरियाणा, जिसने उक्त निर्देशों के आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इन तथ्यों के आधार पर ही वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

3.उनके वकील द्वारा दायर नोटिस के जवाब में, हरियाणा राज्य ने विभिन्न आधारों पर याचिकाकर्ता के मामले का विरोध किया। रिट की विचारणीयता के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया था।

उन्हें विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 33 के तहत दोषी ठहराया गया है। प्रारंभ में, जब यह याचिका इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो हरियाणा राज्य की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई। इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में कुछ विरोधाभास देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 20 अक्तूबर, 1978 के अपने आदेश के तहत इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।

4.संदर्भ पर, यह मामला इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। प्रारंभिक आपत्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए भेजने का विकल्प चुना और इस तरह हम इस मामले को देख रहे हैं।.

5.प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से, श्री नौबत सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता (हरियाणा) द्वारा तर्क

दिया गया था कि 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 58 (2) के प्रावधानों के मद्देनजर वर्तमान याचिका समाप्त हो गई थी, कि 42 वें संशोधन के बाद, प्रभावी या प्रभावोत्पादक उपाय का सवाल ही नहीं उठता था और संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (3) में यह विचार नहीं किया गया था कि ऐसा उपाय प्रभावी होना चाहिए। एक और यह कि चूंकि क़ानून स्वयं केंद्र सरकार के समक्ष एक याचिका के माध्यम से एक और उपाय प्रदान करता है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर रोक लगा दी जाती है।

6.दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वासू द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि खंड (3) के तहत विचार की गई रोक केवल तभी उत्पन्न होती है जब एक और उपाय होता है जो समान रूप से त्वरित, प्रभावोत्पादक और पर्याप्त होता है, कि संसद का ऐसा इरादा संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (1) के उप-खंड (बी) और (सी) को पढ़ने से लगाया जा सकता है। यह कि 'उपाय' शब्द अपने आप में यह बताता है कि यह पर्याप्त और प्रभावोत्पादक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए, कि अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदान किया गया उपाय बिल्कुल भी उपाय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से पहले प्राधिकरण द्वारा उसे नहीं सुना जाता है और अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति विवेकाधीन है।

7. इससे पहले कि मैं विवाद के गुण-दोष पर चर्चा करूं, यह बताया जा सकता है कि 44वें संशोधन के लागू होने के बाद, इस याचिका में बहस के अधीन मुद्दा शायद ही उठेगा जैसा कि उक्त संशोधन, अनुच्छेद 226 के खंड (2) और (3) के अनुसार होगा।

हम चिंतित हैं, हटा दिए गए हैं। एक समय यह सोचा गया था कि नवीनतम संशोधन के परिणामस्वरूप यह प्रारंभिक आपत्ति अपना सारा महत्व खो देगी, लेकिन बहस के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच एस वासू द्वारा यह बहुत ही निष्पक्ष और सही ढंग से स्वीकार किया गया कि कम से कम इस याचिका के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया जाना चाहिए जैसा कि उस प्रारंभिक आपत्ति के हमारे निर्णय की स्थिति में है। राज्य के पक्ष में, याचिका का उपशमन स्वचालित होगा और यही कारण है कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई थी।.

8. पक्षकारों के विद्वान वकीलों के संबंधित तर्क पर, एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या यह रिट याचिका संविधान के 42 वें संशोधन की धारा 58 (2) के प्रावधानों के मद्देनजर समाप्त हो गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने "अधिनियम की धारा 33 में प्रदान किए गए उपाय का लाभ नहीं उठाया है। जो निम्नानुसार है:-

"केंद्र सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकती है और इसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है क्योंकि उसकी राय में मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता है और इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है।

और अनुच्छेद 226 के खंड (3) में होने वाले ऐसे निवारण के लिए कोई अन्य उपाय शब्दों को क्या अर्थ दिया जाना चाहिए।

9. उक्त प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, इस स्तर पर अनुच्छेद 226 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा क्योंकि वे 42 वें संशोधन से पहले और बाद में थे, और 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 58 (1) और (2) के प्रावधान भी, जो निम्नानुसार हैं: -

मूल अनुच्छेद 226	*संशोधित अनुच्छेद* 226
226(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह प्रयोग करता है, शक्ति होगी। अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी,	परन्तु अनुच्छेद 131-क और अनुच्छेद 226-क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त होगी।

मूल अनुच्छेद 226

क्षेत्राधिकार, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिसमें अनुचित मामले भी शामिल हैं, किसी भी सरकार को, उन मामलों के भीतर जारी करना; भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध यथास्थिति वारंट और प्रमाणपत्र, या उनमें से किसी भी रिट की प्रकृति में रिट सहित क्षेत्र निर्देश, आदेश या रिट।

(1-ए) (1) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जिसके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए कार्रवाई का कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।

;' (2) सीएल (1) या सीएल (1-ए) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति सीएल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति का अनादर नहीं करेगी।
1. ओ मैं ! अनुच्छेद 32.

उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में वह किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, जिसमें उपयुक्त मामलों में, कोई भी सरकार, उन क्षेत्रों के भीतर निर्देश या रिट जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और

संशोधित अनुच्छेद 226

सर्टियोरारी, या उनमें से कोई भी शामिल है,
-

1. भाग III के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए; नहीं तो

2. इस संविधान के किसी अन्य उपबंध या किसी अधिनियमन या अध्यादेश के किसी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश, नियम, विनियम, उपविधि या अन्य लिखत के उल्लंघन के कारण पर्याप्त प्रकृति की किसी चोट के निवारण के लिए; नहीं तो

(a) उपखंड (ख) में उल्लिखित किसी उपबंध के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी अवैधता के कारण किसी प्रकार की चोट का निवारण करना, जहां ऐसी अवैधता के परिणामस्वरूप न्याय में पर्याप्त विफलता हुई हो।

मूल अनुच्छेद 226	*संशोधित अनुच्छेद* 226
	1. सीएल (1) द्वारा किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके भीतर ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कार्रवाई का कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।
	1. खंड (1) के उप-खंड (बी) या उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट किसी भी चोट के निवारण के लिए कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इस तरह के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जाता है। *** *

धारा 58 (1) और (2) या 42 वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं: –

संविधान में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन की गई प्रत्येक याचिका और उस दिन के ठीक पहले किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित (ऐसी याचिका को इस धारा में लंबित याचिका के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और कोई अंतरिम आदेश (चाहे निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से) पर किया गया हो, या उससे संबंधित किसी भी कार्यवाही में, उस दिन से पहले ऐसी याचिका को धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधानों या अनुच्छेद 226 के अनुसार निपटाया जाएगा।

10.विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्येक लंबित याचिका, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत स्वीकार नहीं किया गया होता, जैसा कि धारा 388 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यदि ऐसी याचिका दायर की गई थी।

नियत दिन के बाद, ऐसी याचिका से संबंधित किसी भी कार्यवाही में या उससे

संबंधित किसी भी अंतरिम आदेश (चाहे निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से) को निरस्त कर दिया जाएगा< रद्द कर दिया जाएगा।

धारा 58 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि अनुच्छेद 226 में नए संशोधन को उच्च न्यायालय के समक्ष हर लंबित याचिका के रूप में पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत स्वीकार नहीं किया गया होता, जैसा कि 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अगर ऐसी याचिका नियत दिन के बाद की गई थी। अर्थात् 1 फरवरी, 1977 को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, उपशमन मामले का निर्णय केवल इस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार करके किया जा सकता है कि क्या संशोधित अनुच्छेद 226 के तहत, वर्तमान याचिका को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता था या नहीं।

11.संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति बहुत व्यापक थी और इसका प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता था। यह केवल स्व-लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप था कि याचिकाओं पर विचार नहीं किया गया था जहां पर्याप्त वैकल्पिक उपाय मौजूद थे। हालांकि, 42 वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग को खंड (1) में तीन उप-खंड पेश करके प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां तक उपखंड (क) का संबंध है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 226(3) के अंतर्गत यथा परिकल्पित मूल रिट क्षेत्राधिकार को बिना किसी शर्त के अक्षुण्ण रखा गया है। लेकिन उपखंड (ख) और (ग) ने 'अन्य प्रयोजन' के लिए क्षेत्राधिकार के व्यापक दायरे को संविधान के किसी अन्य उपबंध या किसी अधिनियमन या अध्यादेश के किसी प्रावधान या आदेश, नियम, विनियम, उपविधि या उसके अधीन बनाए गए अन्य लिखत के उल्लंघन के कारण किसी चोट के विनिर्दिष्ट प्रयोजन या निवारण तक सीमित कर दिया है, जहां ऐसी चोट पर्याप्त प्रकृति की है; या उपखंड (बी) में उल्लिखित किसी प्रावधान के तहत किसी प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही में किसी अवैधता के कारण किसी भी चोट का निवारण करना, जहां इस तरह की अवैधता के परिणामस्वरूप न्याय की पर्याप्त विफलता हुई है। इसलिए, यदि यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान या आदेशों, नियमों, उपनियमों या उसके तहत बनाए गए लिखतों सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त प्रकृति की चोट पहुंची है और (ii) जहां प्राधिकरण ने उन संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों में से किसी के तहत अपनी कार्यवाही में कोई अवैधता की है और अवैधता के परिणामस्वरूप न्याय की पर्याप्त विफलता हुई है, कि असाधारण शक्ति का प्रयोग किया जा सके। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करने पर, खंड (3) प्रदान करके एक और शर्त रखी जाती है कि उप-खंड (बी) और (सी) शाली में उल्लिखित चोट के निवारण के लिए ऐसी किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.अब यह पता लगाया जाना है कि अनुच्छेद 226 के खंड (3) में 'ऐसे निवारण के लिए कोई अन्य उपाय' शब्दों का उपयोग करने में संसद की क्या मंशा हो सकती है। क्या यह कहा जा सकता है कि इन शब्दों का उपयोग करके संसद का इरादा उन सभी मामलों में न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को रोकना था जिनमें कानून के तहत कोई अन्य उपाय प्रदान किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि किसी दिए गए मामले में ऐसा उपाय भ्रामक, अप्रभावी और प्रभावोत्पादक राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

13.मेरे विचार से, उपर्युक्त समस्या का उत्तर खोजना बहुत दूर नहीं है क्योंकि संसद की मंशा है कि 'उपाय' पर्याप्त, वास्तविक और भ्रामक नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 226 के उप-खंड (बी) और (सी) या खंड (1) से ही कम है। जैसा कि पहले देखा गया है, उप-खंड (बी) और (सी) के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कानून के कुछ संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन या उसके तहत कार्यवाही में प्राधिकरण द्वारा की गई अवैधता के परिणामस्वरूप चोट के निवारण के लिए किया जा सकता है और जहां ऐसी चोट पर्याप्त प्रकृति की है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की पर्याप्त विफलता होती है। लेकिन अनुच्छेद 226 के खंड (3) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लगाए गए आगे के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसी चोट के लिए इसमें दिए गए उपाय का सहारा लेकर कानून के तहत निवारण किया जा सकता है, तो शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां ऐसा उपाय उप-खंड (बी) और (सी) के तहत परिकल्पित निवारण प्रदान करने में असमर्थ है, तो निश्चित रूप से संसद का इरादा कभी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनने और पीड़ित व्यक्ति को उस निरर्थक, भ्रामक या अप्रभावी उपाय के लिए मजबूर करने का नहीं हो सकता है, और अंततः उसे एक अपूरणीय और अपूरणीय चोट पहुंचानी चाहिए। 'उपाय' शब्द अपने आप में यह बताता है कि यह वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए। यदि 'कोई अन्य उपाय' शब्द दिया जाता है, तो उसके द्वारा सुझाया गया अर्थ दिया जाता है। राज्य के लिए विद्वान वकील, फिर किसी दिए गए मामले में पूरा उद्देश्य

खंड (ख) और (ग) निराश हो सकते हैं। यदि कोई वैकल्पिक उपाय खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित चोट का निवारण प्रदान नहीं कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 (3) रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी। तथापि, यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर देखना होगा और यदि वैकल्पिक उपाय प्रदान करने वाले किसी विशेष क़ानून के प्रावधान पर विचार करने के परिणामस्वरूप, खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित चोट के निवारण के लिए एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो ऐसा प्रावधान कोई उपाय नहीं है, तो निश्चित रूप से एक रिट एक उचित उपाय होगा।

14. मैं इस मामले के इस पहलू पर और विस्तार से बात करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि जिस मुद्दे पर हमारे समक्ष बहस हुई है वह कई अन्य मुद्दों की तरह *एक-दूसरे* से जुड़ा नहीं है । उच्च न्यायालयों ने इस मामले की जांच की है और कहा है कि कोई अन्य उपाय ऐसा होना चाहिए जो उप-खंड (ख) और (ग) में विनिदष्ट निवारण प्रदान करने में सक्षम हो। पहला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह *भारत सरकार और अन्य* है। *नेशनल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड* (1), जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:-

> "खंड (3) विशेष रूप से कहता है कि उप-खंड (बी) और (सी) में संदर्भित किसी भी चोट के निवारण के लिए किसी भी रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इस तरह के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय प्रदान किया जाता है। इसलिए, सीएल (बी) द्वारा विचार किया गया 'अन्य उपाय' आवश्यक रूप से वह नहीं होना चाहिए जो किसी संविधि, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियमन, उपनियम आदि के तहत प्रदान किया गया है, जिसके उल्लंघन की शिकायत की गई है। यह पर्याप्त होगा यदि उस अन्य उपाय को कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जाता है। निस्संदेह लागू कानून सामान्य कानून में भी

शामिल होता है। *राशनिंग और वितरण निदेशक* v. *कलकत्ता निगम* (2), *बिल्डर्स सप्लाई कॉर्पोरेशन* बनाम *भारत संघ* (3) *और दौलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य।* (4) इसलिए, यदि कानून द्वारा कोई अन्य उपाय प्रदान किया जाता है, जिसके उल्लंघन की शिकायत रिट याचिका में या लागू किसी अन्य कानून के तहत की जाती है, तो यह रिट याचिका की विचारणीयता पर रोक होगी। लेकिन साथ ही यह याद रखना चाहिए कि 'अन्य उपाय' सक्षम होना चाहिए

1. ए.आई.आर. 1977 ए.पी. 250.
2. ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1355.
3. ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1061.
4. एआईआर 1969 एस.सी. 78.

उप-खंड (ख) और (ग) के अंतर्गत यथा प्रतिपादित ऐसे निवारण का वहन करना। यदि अन्य उपाय पीड़ित व्यक्ति को उप-खंड (बी) या उप-खंड (सी) द्वारा विचार किए गए समान निवारण देने में सक्षम नहीं है, तो इसे रोक नहीं माना जा सकता है। सूट को अपने आप में उपलब्ध एक अन्य उपाय के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। (3) में उल्लिखित 'अन्य उपाय' उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया एक उपाय है। एक सूट को 'अन्य उपाय' के इस व्यापक मिश्रण से बाहर नहीं रखा जा सकता है। हम मध्य प्रदेश राज्य से इस दृष्टिकोण का समर्थन चाहते *हैं भाईलाल भाई* (5), *थमसिंह* बनाम *कर अधीक्षक,* (6) और *टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं, लिमिटेड* बनाम *वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त,* (7).

एक और पहलू को स्पष्ट करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। कुछ समय के लिए उसी कानून के तहत प्रदान किए गए 'अन्य उपाय' के अस्तित्व को हमेशा एक उपाय नहीं कहा जा सकता है जो उप-खंड (बी) या (सी) के तहत प्रदान किए गए ऐसे निवारण देने में सक्षम है। अन्य कानून के तहत प्रदान किया गया अन्य उपाय भ्रामक नहीं होगा। यह वास्तविक होना चाहिए। हम इस पहलू को घर लाने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क़ानून के तहत किसी विशेष प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील प्रदान की गई है, जिसके उल्लंघन की शिकायत की जाती है। लेकिन यदि रिकॉर्ड से यह प्रकट होता है कि प्राथमिक प्राधिकारी ने उच्च प्राधिकारी के निर्देशों या निर्देशों के तहत कार्य किया है, जो अपीलीय प्राधिकारी भी है, तो यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि रिट याचिका उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एक क़ानून या कानून के तहत अपील का अन्य उपाय प्रदान किया गया है। ऐसी घटना में, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील अर्थहीन और भ्रामक होगी, क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण पहले ही इस बिंदु पर एक राय व्यक्त कर चुका है। इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करना सामान्य रूप से वर्तमान अनुच्छेद 226 की मूल भावना और विशेष रूप से सीएल (1) और सीएल (3) के उप-खंड (बी) और (सी) के खिलाफ होगा। शब्द 'इस तरह के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय' महत्वपूर्ण और सार्थक हैं और वे स्पष्ट रूप से किसके इरादे को सामने लाते हैं?

1. ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1006.
2. ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1419.
3.ए.आई.आर., 1967 एस.सी. 1401.

संसद यह मानती है कि केवल वही अन्य उपाय जो वास्तव में और वास्तव में इस तरह के निवारण देने में सक्षम है, जैसा कि उप-खंड (बी) और (सी) में कहा गया है, याचिका की विचारणीयता पर रोक होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या एक रिट याचिका * के मनोरंजन के लिए ऐसी कोई रोक है, न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मांगे गए निवारण और अन्य उपाय की प्रकृति की जांच करनी होगी जो किसी अन्य एलएडब्ल्यू के तहत उपलब्ध हो सकती है। इस संबंध में कठोर और तेज नियम बनाना असंभव और अवांछनीय है।

दूसरा मामला एमपी का है। *राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल* बनाम *क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जबलपुर और एक अन्य*(8), जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया है: –

"खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकार क्षेत्र को अब केवल तभी लागू किया जा सकता है जब इस तरह के निवारण के लिए किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत कोई अन्य उपाय प्रदान नहीं किया गया हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विशेष रूप से कहा कि वर्तमान याचिका उप-खंड (ए) के तहत नहीं आती है और केवल उप-खंड (बी) और (सी) के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए है। संशोधन अधिनियम की धारा 58, इसके बाद पूर्वव्यापी प्रभाव देती है। हालांकि, सीमित तरीके से जितना कि यह रिट याचिकाओं और स्थगन के मध्यस्थ आदेशों पर लागू होता है, जो नियत दिन पर लंबित रहे हैं। अनुच्छेद 226 (3) की भाषा से यह स्पष्ट है कि 'इस तरह के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय' शब्द प्रकट करने में महत्वपूर्ण हैं। संसद की मंशा यह है कि यह आदेश केवल ऐसे मामलों पर लागू होगा जहां अन्य उपाय अनुच्छेद 226 (1) के उप-खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट ऐसे निवारण देने में सक्षम है। इसलिए, यह हमेशा आवश्यक होना चाहिए। न्यायालयों के लिए तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए। प्रत्येक मामला। कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए अन्य उपाय की मांग और इसके परिणामस्वरूप धारा 58 और अनुच्छेद 226 (3) द्वारा लगाए गए दंड की प्रयोज्यता हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं होगा - इस संबंध में कोई कठोर और तेज नियम नहीं© बनाया जाएगा। -

1. ए.आई.आर. 1978 एम.पी.आई.

15.ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, जो स्थिति उभरती है वह यह है कि यदि अनुच्छेद 226 (1) के उप-खंड (एच) और (सी) द्वारा विचार किए गए निवारण के लिए कोई अन्य उपाय प्रदान किया गया है, तो खंड (3) की शर्त लागू होगी और संशोधन अधिनियम की धारा 58 के संचालन से, ऐसे निवारण के लिए नियत दिन पर लंबित याचिकाएं समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले, यह प्रथा कि उच्च न्यायालय उपयुक्त मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार करता था, इस तथ्य के बावजूद कि

एक वैकल्पिक उपाय था और याचिकाकर्ता ने इसका उपयोग नहीं किया था, अब इसे जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करके ऐसी याचिकाओं पर आमतौर पर विचार नहीं करने के लिए स्व-लगाए गए प्रतिबंध को अब वैधानिक प्रतिबंध बना दिया गया है।

तीसरा मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह है *एबैड कॉटन एमएफजी कं, लिमिटेड, आदि।* बहुत। *भारत संघ, आदि।* (9), जहां इसे इस प्रकार देखा गया था: –

"इसलिए, इन निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि जब याचिकाकर्ता को रिट याचिका पर विचार करने से पहले अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अपने वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए कहा जाना है, तो यह अंतर हमेशा सामग्री होगा जहां आदेश क्षेत्राधिकार के बिना या अधिनियम के प्रावधानों या न्याय के आवश्यक सिद्धांतों या किसी अन्य आधार पर अमान्य है जैसा कि *ताराचंद गुप्ता के मामले* में समझाया गया है। *या भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज मामला* या *मो. नूह का मामला* (सुप्रा) और इसलिए, एक कथित आदेश या शून्यता है। ऐसे संदर्भ में वैकल्पिक उपाय एक निरर्थक उपाय होगा क्योंकि, यह चुनौती दिए गए निर्णय में अंतर्निहित शून्यता को प्रभावित नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक अंतर होगा कि पार्टी इस तरह के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था।

16.जैसा कि दाना नाथू *वी में बताया गया* है। *उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, राजकोट (*10), यदि कार्यकारी प्राधिकारी का आदेश एक *अधिकार प्राप्त आदेश है, तो* यह अमान्य होगा और यहां तक कि अगर अपील दायर की जाती है, तो अपील में पुष्टि किए गए आदेश को भी रद्द कर दिया जाएगा।

1. ए.आई.आर. 1977 गुजरात। 113.
2. (1973) 14 गुजरात। एलआर 209 (213)।

शून्यता हो। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां चुनौती इस आधार पर है कि आदेश एक *अति मान्य* आदेश है, वैकल्पिक उपाय को समाप्त करने का सवाल शायद ही उठ सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता सीधे न्यायिक समीक्षा के उपाय की मांग कर सकता है। ये स्थापित सिद्धांत इस संवैधानिक व्यवस्था के बाद और भी अधिक लागू होंगे, जहां अब चोटों के पूर्ण निवारण पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए यह असाधारण उपाय बनाया जाता है ताकि ऐसी गंभीर चोटों में अन्य संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों या अवैधताओं का पालन न करना शामिल हो जो जड़ तक जाते हैं ताकि उन प्रावधानों के तहत काम करने वाले अधिकारियों और न्यायाधिकरणों द्वारा किए जाने पर न्याय की विफलता हो। ऐसे कथित आदेशों के मामलों में एक नागरिक को यह बताया जाना एक खराब सांत्वना होगी कि वह ऐसे उपाय का लाभ उठाए, जिसे वह समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है और जो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा, लेकिन आदेश की पुष्टि होने की स्थिति में एक निरर्थक उपाय होगा क्योंकि यह अभी भी शून्य रहेगा।

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व का ऐसा प्रश्न उठता है तो प्रत्येक अधिनियम की जांच करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि अपील या संशोधन के लिए सामान्य अधिनियम उपायों का क्या औचित्य है ताकि वास्तविक या कथित आदेश का प्रश्न निर्णायक हो। यदि अधिनियम का उपाय इतना व्यापक है कि इसमें कथित आदेशों को भी शामिल किया जा सकता है ताकि प्राधिकरण की गतिविधि का कोई भी हिस्सा संपार्श्विक गतिविधि न हो, तो अधिनियम में इतने व्यापक स्तर तक प्रत्यक्ष उपचार का प्रावधान किया गया है, तो उस उपाय को पहले समाप्त करना होगा। दूसरी ओर, जहां अधिनियम के उपाय इतने व्यापक आयाम के नहीं हैं, बल्कि केवल अधिनियम के तहत आदेशों के लिए हैं, ऐसे कथित आदेशों के मामलों में, अपील उपाय याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आ सकता है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे कथित आदेशों के लिए प्रदान किया गया है जो शून्य और शून्य हैं और जिन्हें याचिकाकर्ता के लिए इस सरल कारण से समाप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। इस तरह का अपील उपाय दोष को ठीक करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही अपील मूल आदेश की पुष्टि करती हो, जिसमें शून्यता का यह अमिट निशान हो।

इसी आशय के लिए रांची क्लब लिमिटेड *बनाम* पटना उच्च न्यायालय के निर्णय हैं /*बिहार राज्य, आदि*(11) और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *श्रीमती इम्तियाज बानो बनाम बिहार मामले में* निर्णय लिया था। *मसूद अहमद जाफरी* आदि, (12)।

17.इस प्रकार उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि अनुच्छेद 226 (3) में होने वाले 'कोई अन्य उपाय' शब्द का अर्थ अनुच्छेद 226 के खंड (1) के उप-खंड (बी) और (सी) में परिकल्पित चोट के लिए राहत प्रदान करने में सक्षम एक वास्तविक उपाय होगा।

18.उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, निर्धारण के लिए अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदान किया गया उपाय उपरोक्त परीक्षण को पूरा करता है। मेरे विचार में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

19.इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उपाय का दायरा क्या है, मेरे लिए इस पहलू पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस संबंध में पहले से ही इस न्यायालय के कुछ निर्णय हैं। पहला निर्णय जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, वह है *रणजीत सिंह* बनाम रणजीत सिंह। *भारत संघ और अन्य* (13), जिसमें यह इस प्रकार मनाया गया है: –

> "हालांकि, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 33 के प्रावधान धारा 24 से बहुत अलग हैं, जिसका शीर्षक "मुख्य निपटान आयुक्त के संशोधन की शक्ति" है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस धारा के तहत दायर किसी भी याचिका को नियमित पुनरीक्षण याचिका के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, धारा 33 का नेतृत्व "केंद्र सरकार की कुछ अवशिष्ट शक्तियां" हैं। दोनों खंडों के कुछ शब्द निस्संदेह समान हैं लेकिन मैं केन्द्र सरकार को धारा 33 के अधीन अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण याचिका के रूप में अथवा नियम 105 द्वारा शासित करने की दृष्टि से किए गए किसी अभ्यावेदन को नहीं मानता हूं। हमारा ध्यान दीवान झंगी राम बनाम डीके महाजन के एक निर्णय की ओर दिलाया गया। *भारत संघ* (14), जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि धारा 33 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को सुना जाना चाहिए, लेकिन उस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को चुनौती देने वाला व्यक्ति एक था।

1. ए.आई.आर. 1978 पृष्ठ 32.
2. ए.आई.आर. 1979 25.
3. 1962 पी.एल.आर.
4. 63 पी.एल.आर. 610.

> जिनके खिलाफ उनके पक्ष में कुछ पिछले आदेश को केंद्र सरकार ने धारा 33 के तहत कार्रवाई करने का दावा करते हुए उलट दिया था, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि यद्यपि अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) में आने वाले शब्द "कोई भी आदेश जो किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस धारा के तहत पारित नहीं

किया जाएगा" धारा 33 में नहीं होता है, वे एक सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं जिसे धारा 33 के तहत कार्य करते समय केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए और इससे पहले कि इस धारा के तहत किसी भी पिछले निर्णय को उलट दिया जाए, जिस व्यक्ति के इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ पहले के फैसले को पलटने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से अनुरोध करने का विकल्प चुनता है, उसे हस्तक्षेप नहीं करने के सरकार के फैसले से पहले आवश्यक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'अगला प्राधिकार बसंत *सिंह जेटली और एक अन्य* व्यक्ति हैं। *मुख्य निपटान आयुक्त और अन्य,* (15), जिसमें एक खंडपीठ के असूचित निर्णय में टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा: –

"इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता के पास विस्थापित व्यक्तियों की धारा 33 के तहत उपलब्ध उपचार का उपयोग नहीं है। अधिनियम मुझे इस मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाने से नहीं रोकता है। मेरा मानना है कि उक्त उपाय समान रूप से प्रभावी और पर्याप्त नहीं होता। प्रतिवादियों के वकील की इस आपत्ति को खारिज किया जाता है।

अगला निर्णय जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, *वह है मेहता लाई चंद* बनाम। *भारत संघ और अन्य,* (16), जिसमें यह इस प्रकार मनाया गया था: –

"पूरी चर्चा का सार और सार यह है कि धारा 33 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों को अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत उपयोग की जाने वाली पुनरीक्षण शक्तियों के बराबर नहीं किया जा सकता है।

1. 1965 करी। लॉ जर्नल (पीबी) 817.
2. ए.आई.आर., 1972, पी. एंड एच. 378.

जिस समय नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने नियम 105 में एक परंतुक जोड़ा, उस समय केंद्र सरकार के समक्ष कार्यवाही के *साथ-साथ* प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित पूरा प्रश्न उसके दिमाग में था। जब इसने अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत किसी याचिका को खारिज करने के संबंध में भी सुनवाई के अधिकार को नकारात्मक कर दिया, तो यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा यह नहीं था कि केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 33 के तहत पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के लिए याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई करनी चाहिए।

अन्यथा मानने से स्पष्ट रूप से बेतुके परिणाम होंगे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जिसका संपत्ति का अधिकार शामिल है और उसकी याचिका को बिना सुनवाई के सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुआवजे के पूल के खिलाफ कोई अधिकार या दावा नहीं करने वाले किसी अजनबी को

अधिनियम की धारा 33 के तहत उसकी याचिका को खारिज करने से पहले सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं निर्णयों को गुणा करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि ऊपर प्रस्तुत टिप्पणियों की समीक्षा पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जो अधिनियम की धारा 33 के तहत याचिका दायर करता है, उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे सुना जाना चाहिए, कि उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकृति की है और इस प्रावधान के तहत कार्यवाही एक संशोधन नहीं है, बल्कि केवल एक अभ्यावेदन है जो किया गया है। केंद्र सरकार अपने विचार के लिए, जिसे बिना किसी मौखिक आदेश पारित किए सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। जैसा कि पहले देखा गया है, इस प्रकार का उपाय न केवल अप्रभावी है, बल्कि अनुच्छेद 226 के खंड (2) के उप-खंड (बी) और (सी) के तहत परिकल्पित चोट को दूर करने में असमर्थ है।

20.मेरे पूर्वोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रारंभिक आपत्ति में कोई दम नहीं लगता है और मैं मानता हूं कि रिट याचिका समाप्त नहीं हुई है। याचिका पर अब एकल न्यायाधीश द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी।.

एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश -मैं सहमत हूँ।
डी.एस. तेवतिया , न्यायाधीश— मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा